

24 मई 2022, नई दिल्ली

जलवायु परिवर्तन में कमी के लिए ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं से संबंधित ईएससीएपी के 78वें आयोग सत्र की साइड इवेंट पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट



उभरती प्रौद्योगिकियां और ऊर्जा क्षेत्र में उनके अभिनव अनुप्रयोग दक्षता में सुधार, उत्सर्जन में कमी और लागत अनुकूलन जैसे लाभ प्रदान करते हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और प्रसार की सुविधा के लिए नीतियों और रणनीतियों को सक्षम करना आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा और पहचान करने के लिए, 23-27 मई 2022 तक ईएससीएपी के 78 वें सत्र के दौरान 24 मई 2022 को एक वर्चुअल साइड इवेंट आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ईएससीएपी के एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, श्री सुरिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव, डीएसआईआर और एपीसीटीटी हेतु राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट (भारत) ने ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के लिए एआई, आईओटी, ब्लॉकचैन और बिग डेटा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया और सदस्य राज्यों के बीच समाधान हेतु काम करने और इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भागीदारी हेतु आहवाहन किया। एपीसीटीटी की प्रमुख डॉ. प्रीति सोनी ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की पहचान करने और ऊर्जा क्षेत्र में सदस्य राज्यों के बीच सीमा पार हस्तांतरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए रणनीतियों का पता लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सुश्री अल्पना दुबे, मिशन की उप प्रमुख, भारतीय दूतावास, बैंकॉक और यूएनईएससीएपी के उप स्थायी प्रतिनिधि ने इस महत्वपूर्ण पक्ष कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आयोजित करने में डीएसआईआर के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि

इस आयोजन के परिणामस्वरूप सभी स्तरों पर सामूहिक कार्रवाई होगी। ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटना। सुश्री आर्मिंडा साल्सियाह अलीस्जाहबाना ईएससीएपी के अवर महासचिव और कार्यकारी सचिव ने अपनी विशेष टिप्पणी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उपयुक्त रणनीतियों पर पहुंचने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

'क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और चुनौतियों' पर विषयगत सत्र का संचालन डॉ. सोनी ने किया। प्रख्यात पैनलिस्टों में (1) डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, (2) डॉ. रोज मवेबाजा, निदेशक और सलाहकार बोर्ड सचिव, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क, (3) प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, और (4) प्रो. पिनाकेश्वर महंत, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश, भारत शामिल थे। पैनलिस्टों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र से सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरणों के साथ क्षेत्र में मौजूदा रुझानों के आधार पर जलवायु परिवर्तन में कमी करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव और सिफारिशें प्रस्तुत कीं। विशेषज्ञों ने मौजूदा चुनौतियों को दूर करने और ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और अनुकूल नीति पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। सदस्य देशों और संस्थानों/संगठनों के प्रतिभागियों ने विशेष रूप से फिलीपींस और पाकिस्तान से बहुत ही जिज्ञासु प्रश्न उठाए। फिलीपींस के प्रतिनिधि ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता की सराहना की और देश में अक्षय ऊर्जा के सफल प्रचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग में भारत सरकार द्वारा की गई नीतियों और उपायों के बारे में पूछा, जिसका भारतीय प्रतिनिधियों ने विस्तार से जवाब दिया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सौर प्रौद्योगिकी पर भारत और फ्रांस के बीच समझौते के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि की राय थी कि सामुदायिक विकास के लिए भागीदारी महत्वपूर्ण है और सौर पैनल बेचने के लिए महिलाओं को सूचीबद्ध किए जाने पर आईएसए के बयान को स्वीकार किया जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण में महिलाओं और समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करने वाला एक उत्कृष्ट उदाहरण साबित होता है। उन्होंने भारतीय वक्ताओं से जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी और लिंग या हरित बंधन की भूमिका और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण भागीदारों की भागीदारी को दर्शाते हुए अधिक उदाहरण साझा करने का अनुरोध किया।

सदस्य देशों द्वारा सौर फोटोवोल्टिक की सतत तैनाती और इस दिशा में क्षमता निर्माण की आवश्यकता संबंधित अन्य प्रश्न भी उठाए गए थे। प्रतिभागियों से कुछ मूल्यवान सुझाव भी प्राप्त हुए जैसे एक प्रतिभागी ने कहा कि नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों, व्यावसायीकरण और सभी हितधारकों के लिए इसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह, एक और सुझाव प्राप्त हुआ कि सभी भाग लेने वाले देशों में युवा उद्यमियों और एसएमई के लिए नीतियों की उपयुक्तता भी बहुत महत्वपूर्ण है और एपीसीटीटी को इस संबंध में उचित उपाय करने चाहिए।

कार्यक्रम का समापन डॉ.रामानुज बनर्जी, वैज्ञानिक 'एफ', डीएसआईआर और एपीसीटीटी के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट (इंडिया) के टिप्पणी के साथ हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में इस धरती पर जलवायु परिवर्तन में कमी हेतु उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सदस्य राज्यों

द्वारा सहयोग की एक स्पष्ट दृष्टि और सुदृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। इस साइड इवेंट में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और जलवायु परिवर्तन में कमी के लिए ऊर्जा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और अपनाने की सुविधा के लिए रणनीतियों के संबंध में विचार-विमर्श हेतु सदस्य राज्यों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और प्रतिभागियों के लिए एक मंच प्रदान किया।

---